

उपखण्ड अधिकारी केकड़ी जिला -अजमेर(राजस्थान)  
राजस्व प्रार्थना पत्र 124 / 2019 (2019 / 00386)

श्री पुत्री नारायण पत्नि छोदू जाति दरोगा उम 70 वर्ष निवासी श्रीराम कॉलोनी केकड़ी तहसील केकड़ी जिला अजमेर राजस्थान -----प्रार्थी

बनाम

1. महावीर पुत्र नारायण जाति दरोगा(वालिंग)
2. बल्लू पत्नि प्रहलाद जाति दरोगा (वालिंग)
3. राजू पुत्र प्रहलाद जाति दरोगा (वालिंग)
4. हेमराज पुत्र प्रहलाद जाति दरोगा(वालिंग)
5. मोनू पुत्र प्रहलाद जाति दरोगा (वालिंग)
6. लालाराम पुत्र प्रहलाद जाति दरोगा (वालिंग)
7. श. पुत्र नारायण जाति दरोगा (वालिंग)

निवासीकेकड़ी केकड़ी तहसील केकड़ी जिला अजमेर राजस्थान

8. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार महोदय केकड़ी

9. मैसर्स श्री नाथ माईन्स एण्ड गिनरल्स केकड़ी जरिये पार्टनरर्स

- 9(1) रामअवतार डोडिया पुत्र रामप्रताप डोडिया निवासी केकड़ी
- (2) बालकिशन साहू पुत्र गजानन्द साहू जाति तेली निवासी केकड़ी
- (3) बिरदी चंद डाडीया पुत्र रामप्रताप डोडिया निवासी केकड़ी
- (4) निलेश कर्नावट पुत्र सुशील कर्नावट निवासी केकड़ी

—अप्रार्थीगण

अंतर्गत धारा 212 राजस्थान कार्तकारी अधिनियम

उपरिथत:- श्री नवल पारीक वकील -प्रार्थीयां

श्री ए0 एस0 गौरी वकील- अप्रार्थीगण संख्या 1 से 07

श्री बद्री विशाल दाधीच - अप्रार्थी संख्या 9(1 से 4)

आदेश

दिनांक 02.09.2021


संक्षेप मे प्रकरण के तथ्य इस प्रकार से है कि कसबा केकड़ी की निम्नवर्षि आराजीयात जमाबंदी संवत् 2061-2064 मे स्थित है:-

खाता संख्या नया-पुराना	खसरा नंबर	रकबा (है0)	किरम
1314-1311	4813	0.08	वारानी 2
	4814	0.02	गै.मु.चाह
	4817	0.66	चाही 2
	4818	0.15	चाही 2
	4819	0.37	चाही 2
	4820	2.61	वा.2
	4821	0.08	गै.मु.पाल
	4822	0.08	गै.मु.पाल
	4828	1.15	वा.2
	4829	0.02	गै.मु.पाल
	4946	0.15	गै.मु.पाल
	4947	0.20	गै.मु.पाल
	4948	0.26	गै.मु.पाल
	4949	2.43	वा.1
	4950	0.04	गै.मु.पाल

उपखण्ड अधिकारी  
केकड़ी (अजमेर)

वर्णित आराजीयात प्रार्थियों की पुश्तैनी आराजीयात है जो प्रार्थियों के दादा श्री बालू पुत्र रोडा के नाम राजस्व रेकार्ड 1349 फरसली में बतौर खातेदार के दर्ज है तथा उनकी मृत्यु के बाद बालू पुत्र रोडा के एक मात्र विधिक वारिस नारायण के नाम बतौर खातेदारी में आराजीयात रेकार्ड में दर्ज की गई। नारायण पुत्र बालू जाति दशेगा प्रार्थियों का पिता है तथा प्रार्थियों के मृत्यु हो चुकी है, तथा उनकी मृत्यु के उपरांत प्रार्थियों व अप्रार्थी संख्या 1 व प्रहलाद व अप्रार्थी संख्या 07 उनके विधिक वारिसान है। प्रहलाद की मृत्यु हो चुकी है, तथा अप्रार्थी संख्या 02 लगायत 06 प्रार्थियों का पुश्तैनी आराजीयात में जन्म से ही हक अधिकार हिस्सा निहित है तथा प्रार्थियों के पिता के उपरांत प्रार्थियों अपने हिस्से के 1/4 हिस्से को काश्त कर उपज प्राप्त करती चली आ रही है, अप्रार्थीगण का प्रार्थियों के 1/4 हिस्से में किसी प्रकार का हक अधिकार हिस्सा नहीं है। अप्रार्थीगण प्रार्थियों के पिता की मृत्यु के उपरांत राजस्व अधिकारियों से मिलीभगत कर नामान्तरकरण स्वयं के नाम दर्ज करवा लिया है, जबकि स्वर्गीय नारायण की जायंदा पुत्री का नाम राजस्व रेकार्ड में दर्ज नहीं किया है, जो दुरुस्त किये जाने योग्य है। अप्रार्थीगण दिनांक 06.10.2017 को प्रार्थियों के हक हिस्से के 1/4 पर अप्रार्थीगण एकराय होकर आये और प्रार्थियों को आराजीयात से जबरन वेदखल करने की शिष्ट से लड़ाई झगडा करने लगे और प्रार्थियों को धमकी दी कि आराजीयात राजस्व रेकार्ड में हमारे नाम दर्ज है हम उक्त आराजीयात को अन्य दीगर व्यक्ति को बेचान कर तुझे वेदखल करेगे तुम हमारा कुछ नहीं बिगाड सकती हो अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थियों को धमकी देने के पश्चात राजस्व रेकार्ड की जानकारी करी तो जानकारी में आया कि प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजीयात में प्रार्थियों का नाम बतौर बिरासत के नामान्तरकरण में दर्ज नहीं किया गया है तथा उपरोक्त आराजीयात गलत रूप से अप्रार्थीगण के नाम हो जाने से अप्रार्थीगण प्रार्थियों को आराजीयात से वेदखल कर आराजीयात को बेचान करने पर आनादा है तथा आराजीयात को बेचान करने की आयेदिन धमकिया दे रहे है इसलिए यह वाद प्रस्तुत करना लाजमी आया है। अप्रार्थीगण अपने नाजायज उद्देश्य में कामयाब हो जाते है तो प्रार्थियों अपनी पुश्तैनी आराजीयात से वेदखल हो जायेगी। जिससे प्रार्थियों को अनेकानेक कठिनाईयां का सामना करना पड़ेगा। प्रार्थियों का प्राईमाफैसाई केस है सुविधा का संतुलन भी प्रार्थियों के पक्ष में है। अप्रार्थीगण उनके मुखवार, नोकर चाकर हाली सिरि आदि को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा पाबंद किया जावे कि प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजीयात को किसी अन्य दीगर व्यक्ति को रहन बेचान बक्षीस इत्यादि नहीं करे और ना ही प्रार्थियों के कब्जे स्वामित्व में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न करे। यानि की वाद वर्णित आराजीयात के बाबत राजस्व रेकार्ड की स्थिति को यथावत् बनायी रखी जावे। प्रकरण श्रवणाधिकार व क्षेत्राधिकार का होने से दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया।

अप्रार्थीगण की ओर से जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत हुआ जिसमें प्रार्थियों द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में अंकित कथनो का खण्डन प्रस्तुत किया गया अतिरिक्त कथन में बताया कि प्रार्थियों द्वारा दिनांक 28.10.2017 को प्रार्थना पत्र संख्या 136/2017 मान्य हाजा में बउनवान भूरी बनाम महावीर प्रस्तुत किया। उस प्रार्थना पत्र में अंतरिम स्थगन आदेश जारी किये गये जिसमें माननीय न्यायालय उपखण्ड अधिकारी केकड़ी द्वारा गौका व रेकार्ड की आगामी पेशी तक यथास्थिति बनाये रखने व स्थगन आदेश को जर्गे रजिस्टर्ड ए0डी0 से तलबी ना करने पर स्थगन आदेश स्वतः निरस्त माना जावे कि तहरीर अंकित की गई है। जिसमें आगामी पेशी दिनांक 10.01.2018 को पेशी मुकरर की गई तथा उक्त विवादित आराजीयात बाबत में प्रार्थियों द्वारा माननीय न्यायालय द्वारा पूर्व में ही वाद व प्रार्थना पत्र विचाराधीन होने के बावजूद पुनः एक प्रार्थना पत्र व वादपत्र दिनांक 23.01.2019 को मान्य हाजा में प्रार्थना पत्र संख्या 13/2019 बउनवानी भूरी बनाम महावीर वगैराह प्रस्तुत किया है जिसमें उक्त प्रार्थना पत्र में भी मान्य न्यायालय उपखण्ड अधिकारी केकड़ी द्वारा अन्तरिम आदेश जारी कर दिया गया व आगामी पेशी दिनांक 11.09.2019 को मुकरर की गई इस प्रकार प्रार्थियों द्वारा समान पक्षकार, समान विवादित आराजीयात व समान विषयवस्तु दिनांक 06.10.2019 को लेकर प्रार्थियों द्वारा

  
उपखण्ड अधिकारी  
केकड़ी (अजमेर)


आर्थाई निषेधाज्ञा के लिए दिनांक 28.10.2017 व दिनांक 23.01.2019 समान विवाद के लिए दो प्रार्थना पत्र आर्थाई निषेधाज्ञा हेतु प्रस्तुत किया गया जिसमें माननीय न्यायालय द्वारा पूर्व में ही स्थगन आदेश जारी कर दिये गये थे। फिर भी प्रार्थीयां द्वारा न्यायालय को मुगालते में रखकर समान विवाद हेतु उक्त विवादित निम्न वर्णित आराजीयात में माननीय न्यायालय द्वारा अन्तरिम स्थगन जारी करवा लिये गये जो विधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 11 के अनुसार पूर्व न्याय के सिद्धान्त के आधार पर खारिज किये जाने योग्य है क्योंकि उक्त विवाद विषयवस्तु के संबंध में पूर्व में ही निर्णित किया जा चुका है। इस उक्त प्रार्थना पत्र व बाद खारिज किये जाने योग्य है। प्रार्थना पत्र वेग अस्पष्ट व अनिश्चितता का होने से खारिज होने योग्य है। प्रार्थीयां को इस प्रकार का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने का कोई विधिक अधिकार व वेग स्टण्डाई नहीं है। प्रार्थीयां का प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने योग्य है। वाकातन व कानूनन भी प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने योग्य है। जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर वकील पक्षकारान की बहस सुनी गई-

आदेश सुनाने से पूर्व श्री सूर्यकान्त दाधीच एडवोकेट के जरिये प्रार्थीगण मैसर्स श्रीनाथ माईन्स एण्ड मिनरल्स केकड़ी जरिये पार्टनर प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 01 नियम 10 जाफ़ा दीवानी प्रस्तुत किया। जिस पर वकील प्रार्थीयां एवं अप्रार्थीगण की बहस सुनी गई। प्रार्थीया के अभिभावक द्वारा पक्षकार बनाये जाने की आपत्ति की गई। अधिवक्तगण की बहस पर मनन किया गया। न्यायालय द्वारा आदेश 01 नियम 10 सीपीसी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया गया। प्रार्थीयां के अधिवक्ता द्वारा संशोधित प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। अप्रार्थी संख्या 09 की ओर से जवाब प्रस्तुत किया गया जिसकी प्रति वकील प्रार्थीयां को दी गई। तत्पश्चात प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 आरटी0ए0 पर पुनः बहस सुनी गई।

प्रार्थीयां के लायक वकील श्री नवल किशोर पारीक ने अपनी बहस में बताया कि प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजी पुश्तैनी है। यह आराजी पूर्व में बालू की थी। बालू की मृत्यु के बाद यह आराजी जरिये विरासत नारायण पि0 बालू के खाते में दर्ज हुई है। प्रार्थीयां नारायण की पुत्री हैं अतः प्रार्थीयां का जन्म से इस आराजी में हक अधिकार है। अपने कथन के समर्थन में प्रार्थीयां/टीए/4311/2012/जोधपुर संगत सिंह व अन्य बनाम जब्बर सिंह व अन्य निर्णय दिनांक 29.01.2020 प्रस्तुत की जिसका ससम्मान अध्ययन किया गया। नगर पालिका केकड़ी से जारी सजरा प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया।

अप्रार्थीगण के लायक अधिवक्ता श्री अब्दुल सलीम गौरी ने अपने वितर्क प्रस्तुत करते हुए कथन किया कि प्रार्थीयां ने कोई सजरा पेश नहीं किया है। आराजी पैतृक होने का कोई दस्तावेज संलग्न नहीं है। प्रार्थीयां भूरी नारायण की बेटी हो यह साबित नहीं किया है। रिकार्डेड खातेदार के खिलाफ अस्थाई निषेधाज्ञा आदेश प्रसारित नहीं किया जा सकता है। नारायण के फौत होने पर नामान्तरकरण नियमानुसार खोला गया है। प्रार्थीयां अजगन्बी हैं उराका इस आराजी से कोई वारंता व अधिकार नहीं है। इस प्रकरण में प्रार्थीयां ने दो अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये हैं जो चलने योग्य नहीं हैं। अतः प्रार्थना पत्र बाबत अस्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करने खारिज किया जावे। अपने कथन के समर्थन में विधानसभा क्षेत्र केकड़ी की नामावली 1998 भागसंख्या 112 प्रस्तुत की है जिसमें प्रार्थीयां का नाम अंकित नहीं होना जाहिर किया। प्रहलाद पि0 नारायण, महावीर पि0 नारायण का राशन कार्ड प्रस्तुत किया है जिसमें भी प्रार्थीयां का नाम होना जाहिर नहीं है। न्यायिक दृष्टान्त आरआरटी 2014(1) श्यामकौर व अन्य बनाम राजस्थान सरकार व अन्य पी.59 11/12.06.14, आर0वी0जे0 2018 499 रवि माहेश्वरी बनाम परमेश्वरी देवी, आरआरटी प.69 11/12.06.12 कर्मिल व अन्य बनाम लालू, आरआरटी पी 63 11/12.12.2014 गोपाराम व अन्य बनाम हरिमाराम व अन्य आरआरटी पी.7611/12.06.2011 मूलचंद बनाम हनुमान प्रसाद व अन्य प्रस्तुत किया जिनका ससम्मान अध्ययन किया गया।

अप्रार्थी संख्या 09 के लायक वकील श्री एस0के0 दाधीच एडवोकेट ने अपनी बहस में बताया कि दिनांक 03.09.2020 को खसरा नंबर 4949 रकबा 1.34 हे0 में से 1.34 हे0 हमारे द्वारा कय कर ली है, हमने जमाबंदी देखकर कय की है जमाबंदी में स्थगन आदेश का अंकन नहीं था, अप्रार्थी संख्या 09 सद्भाविक कंता है तथा आराजी कय शुदा का प्रतिफल रिकार्डेड खातेदार अप्रार्थी संख्या 01 से 07 को अदा कर विकय पत्र नियमानुसार पंजीकृत करवाया है। प्रार्थीयां- अप्रार्थीगण की बहिन नहीं है। यदि बहिन होती तो अप्रार्थीगण प्रार्थीयां को बहिन मानने से हिन्दु कस्टम के आधार पर

  
 उपखण्ड अधिकारी  
 केकड़ी (अजमेर)

ना नहीं कर सकते थे, प्रार्थीयां -अप्रार्थीगण संख्या 01-07 की वहिन-भुआ होती, तो अप्रार्थीगण वहिन भुआ मानने से मना नहीं करते। प्रार्थीया द्वारा जो अध्यक्ष नगर पालिका केकडी द्वारा जारी सजरा प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया है। जो कानूनी नहीं है। पारिवारिक सजरा प्रमाण पत्र पर अधिशापी अधिकारी हस्ताक्षर नहीं है। नगर पालिका केकडी को पारिवारिक सजरा प्रमाण पत्र जारी करने का अधिकार नहीं है। यह पारिवारिक सजरा प्रमाण पत्र अध्यक्ष नगर पालिका केकडी द्वारा बिना अधिकारिता के जारी किया गया है, जो स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है। प्रार्थीयां के लायक अभिभाषक ने प्रति उत्तर में बताया कि आज की तारीख में एक ही दावा व एक ही अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र विचाराधीन न्यायालय में है। प्रार्थीयां नारायण की पुत्री है या नहीं यह मूल वाद में वाद शहादत तय होगा। आज की प्रश्न यह है कि प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजी पर यथार्थिति के आदेश प्रसारित किये जाना है। प्रार्थीयां का प्राईमाफैसाई केस है सुविधा का संतुलन भी प्रार्थीया के पक्ष में है। अतः अप्रार्थीगण को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा पाबंद किया जावे कि की वे प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजीयात पर यथार्थिति बनाये रखे। राजस्व रेकार्ड में कोई परिवर्तन नहीं करे। अप्रार्थी संख्या 09 द्वारा स्थगन आदेश के बावजूद कय की है जिसका नामान्तरकरण नहीं किया जावे। अप्रार्थीगण को प्रार्थीयां के कब्जे स्वामित्व में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं करने हेतु अप्रार्थीगण 1 लगायत 09 को मूल वाद के निस्तारण तक अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना फरमावे।

वकील पक्षकारान की बहस पर गौर किया। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया। वकील पक्षकारान द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्त का ससम्मान अवलोकन किया गया। न्यायालय को फिलहाल यह देखना कि प्रार्थीयां अस्थाई निषेधाज्ञा आदेश प्राप्त करने की हकदार है अथवा नहीं ? प्रार्थीयां द्वारा अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने हेतु तीनो आवश्यक बिन्दु यथा प्रथम दृष्टया केस, सुविधा का संतुलन, अपूर्णनीय क्षति के बिन्दु अपने पक्ष में साबित किये हैं साथ ही अप्रार्थी संख्या 09 द्वारा विक्रय पत्र पंजीयन अधिकारी के कार्यालय में नियमानुसार स्टाम्प ड्युर्ट पंजीयन करवाया है। जमाबंदी देखकर आराजी कय की है। प्रार्थीया का नाम जमाबंदी में अंकित नहीं है और न ही किसी न्यायालय से स्थगन आदेश होने का नोट अंकित था। अप्रार्थी संख्या 09 द्वारा करवाया गया विक्रय पत्र आज दिनांक तक किसी भी न्यायालय से खारिज भी नहीं हुआ है। अप्रार्थी संख्या 09 सदभाविक क्रेता है। अतः विक्रय पत्र के आधार पर नामा0 किया जाना न्याय संगत है। वैसे नामान्तरण की कार्यवाही को फिसकल प्रोसेडिंग माना गया है। अतः अप्रार्थी संख्या 09 के पक्ष में विक्रय पत्र के आधार पर नामा0 की कार्यवाही नियमानुसार की जावे। प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजी इन मीडिय है, तथा भविष्य में अनावश्यक विवाद उत्पन्न होने से रोकने की दृष्टिगत रखते हुए, अप्रार्थी संख्या 01 07 तथा नियमानुसार विक्रय पत्र के नामान्तरण पश्चात अप्रार्थी संख्या 9 को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा पाबंद किया जाता है कि वे मूल वाद के निस्तारण तक हस्तगत प्रकरण में वर्णित आराजी का अब और आगे अन्य व्यक्ति को विक्रय, हस्तान्तरण, रहन, बक्षीस नहीं करे तथा मौके एवं रिकार्ड की यथार्थिति बना रखे। यह प्रार्थना पत्र हक अधिकार का अंतिम निर्धारण नहीं करता है हक अधिकार का निर्णय मूल वाद में वाद शहादत तय होगा। खर्चा फरिकेन अपना अपना वहन करे। आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(विकास पंचोली)  
उपखण्ड अधिकारी  
केकडी (केकडी नगर)